मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2018-20 /R.N.I. No. 66400/97

किसानों और खट्टर का रविवार को सीधा टकराव 3
जाते-जाते किनकी फ़ाइलें निपटा गए निगम कमिश्नर 4
किसानों के 'मसीहा' की ऊंची उड़ान 5
किसान सत्याग्रह में राजकीय हिंसा का प्रवेश न हो जाए 6
निकिता मामले में फिर गरमाई राजनीति 8

वर्ष 34 | अंक 9 | फरीदाबाद | 10-16 जनवरी 2021 | फोन-8851091460 | 3.00 ₹

तुग़लक़ी नीति साबित हो रहा है परिवार पहचानपत्र

आधार, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, पैन कार्ड के बावजूद इसकी ज़रूरत क्यों ?

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार की तुग़लक़ी नीतियों ने आम लोगों की ज़िन्दगी दूभर कर दी है। 6 जनवरी को सरकार ने सभी पेंशन स्कीमों को फ़ैमिली आईडी (परिवार पहचानपत्र-पीपीपी) से जोड़ कर आईडी को अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा सरल पोर्टल की 114 सरल सेवाओं को भी इससे जोड़ दिया गया। यानी जिसने फ़ैमिली आईडी नहीं बनवाई है उसे किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कुल 544 सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा जाएगा।

यह तुग़लक़ी नीति क्यों है

खट्टर सरकार पीपीपी बनाने के लिए आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड माँग रही है। जिनके पास आधार, पैन या राशन कार्ड में से कोई भी आईडी नहीं है, उसका परिवार पहचान पत्र नहीं बनेगा। स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार आपका डेटा वहाँ से उठाकर अपने सिस्टम में डालेगी और आपको 14 अंकों का एक यूनीक आईडी नंबर जारी कर देगी।

आधार और पैन के ज़रिए भारत सरकार के पास सभी का डेटा पहले से ही मौजूद है। फिर आख़िर एक और सरकारी आईडी बनाने की ज़रूरत हरियाणा सरकार को क्यों पड़ रही है। तमाम जिलों में राज्य के अधिकारी सरकार के इस तुग़लक़ी फ़रमान पर सिर धुन रहे हैं। लोग पीपीपी बनवाने

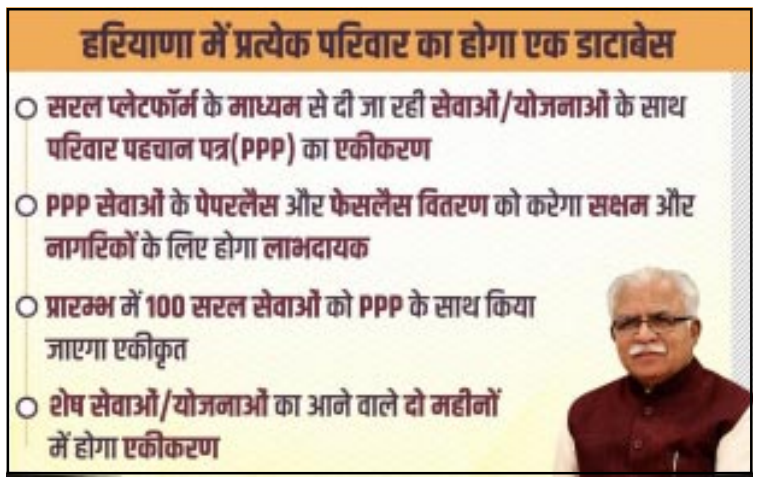

को लेकर दफ़्तरों में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से बहस करते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब उनके पास आधार है तो यह कार्ड किसलिए? किसी के पास इसका जवाब नहीं है। लोग झल्लाहट में सीएम खट्टर के पास जाने की सलाह देते हैं। सरकार का कहना है कि वह सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए ऐसा कर रही है।

इन योजनाओं को जोड़ा

समाज कल्याण विभाग की सभी पेंशन योजनाएँ, शहरी निकाय विभाग, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, फूड सप्लाई, श्रम विभाग, स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा, हाउसिंग बोर्ड, वन विभाग, रोज़गार विभाग, उद्योग और वाणिज्य विभाग, पर्यटन विभाग, खेल, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, गृह विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं सहित अनगिनत विभागों को इससे जोड़ दिया गया है। अटल सेवा केन्द्रों, सीएससी सेंटर, कुछ सरकारी स्कूलों में पीपीपी बनवाने की व्यवस्था कराई गई है।

मुफ़्त का दावा, पर बिना पैसे काम नहीं

हरियाणा सरकार का निर्देश है कि पीपीपी कार्ड बिल्कुल मुफ़्त बनाया जाए। लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि सौ रूपये से लेकर दो सौ रूपये तक ही ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। यह अकेला हाल फरीदाबाद जिले का ही नहीं है। पूरे प्रदेश से यही सूचनाएँ हैं। खुद हरियाणा के सीएम खट्टर के मुताबिक़ घरौंडा के कुटैल गाँव में सीएससी सेंटर पर पैसे लेकर पीपीपी कार्ड बनाया जा रहा था। इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है और सीएससी सेंटर की लॉग इन आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है।

ज़्यादातर सीएससी सेंटर भाजपा कार्यकर्ताओं को चलाने के लिए दिए गए हैं। कुछ ने इसे सेवाभाव के तहत कमाई का ज़रिया बना लिया है। कहीं कहीं तो भाजपा नेता पीपीपी कार्ड बनवाने के नाम पर राजनीति भी कर रहे हैं।

पीपीपी का पूरा सिस्टम आधार कार्ड बनाने वाले अभियान जैसा हो गया है। शुरू शुरू में जिस तरह विभिन्न सामाजिक संगठनों और आरडब्ल्यूए ने आधार के लिए कैंप लगवाए और सबसे पहले अपने व रसूखदार लोगों के आधार बनवाए। ठीक वही तरीक़ा पीपीपी में भी अपनाया जा रहा है।

कोरोना वैक्सीन को पीपीपी से जोड़ा

हरियाणा की जनता, अफ़सर और कर्मचारी इस योजना को एक और वजह से तुग़लक़ी कहना शुरू कर दिया है। हरियाणा सरकार और फरीदाबाद के डीसी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन उसी को लगेगी जिसके पास पीपीपी कार्ड होगा। जनता का कहना है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन तो घोषणा कर चुके हैं कि सभी को वैक्सीन मुफ़्त मिलेगी, फिर इसे पीपीपी से जोड़ने का क्या अर्थ है? अगर वैक्सीन को आधार से जोड़ा जाता तो भी कुछ समझदारी की बात होती।

पिछले हफ़्ते फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव ने एक बैठक में अधिकारियों से कहा था कि एकदम चुनावी मोड में कोरोना टीकाकरण अभियान चलेगा और टीका उनको लगेगा, जिनकी जानकारी फ़ैमिली आईडी में होगी।

खट्टर के सपने पर भारी पड़े लोग

मुख्यमंत्री ने पीपीपी लॉन्च करते हुए कहा था कि इसके ज़रिए राज्य में सबसे कम आमदनी वाले एक लाख परिवारों का चयन कर उनकी आमदनी बढ़ाने का अभियान चलाया जाएगा।

इसका नतीजा यह निकला कि बड़े पैमाने पर लोगों ने ग़लत जानकारियाँ भर दीं। जिनके पास दस एकड़ ज़मीन थी, उन्होंने ज़ीरो भरा। नौकरीपेशा लोगों ने अपनी सालाना आमदनी तीस से पचास हज़ार लिख दी। अगर किसी घर में चार लोग हैं तो पिता और बेटे ने अलग अलग आईडी बनवा ली है।

हाल ही में हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने जब आँकड़ों की छानबीन की तो पता चला कि राज्य में 12 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सालाना आमदनी पचास हज़ार रूपये से भी कम दिखाई है। अब सरकार ऐसे परिवारों की जाँच कराने की बात कहकर लीपापोती कर रही है।

कोई चुनौती नहीं दे रहा

परिवार पहचानपत्र को हरियाणा में हर योजना के लिए ज़बरन अनिवार्य किए जाने को अभी तक किसी राजनीतिक दल, संगठन, वक़ील, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किसी अदालत में चुनौती नहीं दी है। आधार को लेकर उठे विवाद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उसी चुनौती के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस समय हर सेवा के लिए आधार को अनिवार्य बनाने से इन्कार कर दिया था। अभी जिस तरह हरियाणा के लोग पीपीपी बनवाने को लेकर परेशान हैं, इसे चुनौती दी जानी चाहिए। चुनौती देने की सबसे बड़ी वजह तो कोरोना वैक्सीनेशन को इससे जोड़ा जाना ही काफ़ी है। कोरोना वैक्सीन पाना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, उसे पीपीपी से कैसे जोड़ा जा सकता है? यह वजह चुनौती के लिए पर्याप्त है।

डीएल: एसडीएम बल्लभगढ़ दलालों की लूट तो रोक सकती हैं, लेकिन सरकार की नहीं

ऑनलाइन का ड्रामा ज्यादा, खुद जाना पड़ता है हर जगह

चन्द्रप्रकाश

बल्लभगढ़ : एसडीएम दफ़्तरों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को सरकार और अधिकारियों ने अपनी लूट व कमाई का एक बड़ा साधन बना लिया है। एसडीएम बल्लभगढ़ अपराजिता ने अपनी कर्त्तव्य निष्ठा के चलते दफ्तरी बाबुओं व दलालों की लूट पर अंकुश लगाने का भरपूर प्रयास किया है। सरकार द्वारा की जा रही लूट को रोक पाना उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ऑनलाइन डीएल बनवाने का नाटक हर एसडीएम दफ़्तर में चल रहा है।

लर्नर लाइसेंस ऐसे बना

इस संवाददाता ने यह सारा अनुभव अपना खुद का लाइसेंस बनवाकर हासिल किया। लाइसेंस बनवाने के लिए यह संवाददाता एसडीएम बल्लभगढ़ कार्यालय

पहुंचा और साइबर कैफे वाले को 30 रु देकर ऑनलाइन फाइल बनवाई। इस फाइल को लेने के बाद बताया गया कि 300 रु की पर्ची रेडक्रास कार्यालय सेक्टर-12 में कटेगी यानि कि रेडक्रास को 300 रु देने के लिए 5 किमी की यात्रा करनी पड़ी। वहां पहुंचने पर बताया गया कि वे 300 रू नकद नहीं लेते इसे ऑनलाइन जमा कराना होगा। इसके लिए 80 रु बाहर बैठे साइबर कैफ़े वाले को देने पड़े, यानि 300 वाला काम 380 रु में पड़ गया, और धक्के खाये अलग से।

रेडक्रास के नाम पर भी लूट

इसके बाद शुरू होती है रेडक्रास द्वारा प्राथमिक चिकित्सा की ड्रामेबाजी वहां से प्रशिक्षण लेने के लिए कोई तारीख दी जाती है। इस ड्रामेबाजी से बचने के लिए बाबुओं को सुविधा शुल्क देकर भी निकला जा सकता है। इसके बाद वापस बल्लबगढ़ एस.डी.एम. ऑफिस आने के बाद वहीं पर बैठे एक डॉक्टर से प्रमाणपत्र लेने के लिए 150 रु की पर्ची नकद कटवाई गई। इसके बाद पुलिस विभाग द्वारा ट्रैफ़िक नियम संबंधी टेस्ट लिया जाता है। इसके लिए भी 650 रु की फीस लगी। जिसे ऑनलाइन जमा कराने के लिए 80 रु बाहर बैठे साइबर कैफ़े वाले को देने पड़े यानि कि 650 के काम के 730 रु देने पड़े। इसके दो दिन बाद लर्नर लाइसेंस बन गया।

पक्के लाइसेंस में भी धांधली

इसके 42 दिन बाद पक्के लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके लिए 30 रु की फिर से ऑनलाइन फाइल बनवाई गई। उसके बाद यह संवाददाता

शेष पेज चार पर